<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इरेडा के सीएमडी ने विश्व बैंक वेबिनार को संबोधित किया; आरई लक्ष्यों के लिए 30 लाख करोड़ रुपये की रूपरेखा निवेश की आवश्यकता

इरेडा के सीएमडी ने नवीकरणीय ऊर्जा रोल मॉडल के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली, 14 फरवरी

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री प्रदीप कुमार दास ने आज विश्व बैंक जेनेवा द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया। यह वेबिनार नवीनतम साऊथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट "टुवार्ड फास्टर, क्लीनर ग्रोथ" के जारी होने के अवसर पर आयोजित किया गया था।
अपने संबोधन में, इरेडा के सीएमडी ने वर्ष 2030 तक भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय वर्ष 24-30 की अवधि में 30 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने निवेश की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया, जिसमें विशेष रूप से सोलर, हाइड्रो, विंड और अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा विनिर्माण निवेश (सोलर, इलेक्ट्रोलाइज़र, विंड और बैटरी), ट्रांसमिशन, ग्रीन हाइड्रोजन शामिल हैं।

इसके अलावा, श्री दास ने 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई रुफ़टॉप सोलर स्कीम, "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" के महत्व पर भी प्रकाश डाला । यह दूरदर्शी परियोजना, 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश द्वारा समर्थित है, का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है। इरेडा के सीएमडी ने स्पष्ट किया कि यह पहल देश में रूफटॉप सोलर क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना न केवल पर्याप्त लाभ प्रदान करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी, और वर्ष 2070 तक नेट-शून्य उत्सर्जन और वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान देगी।

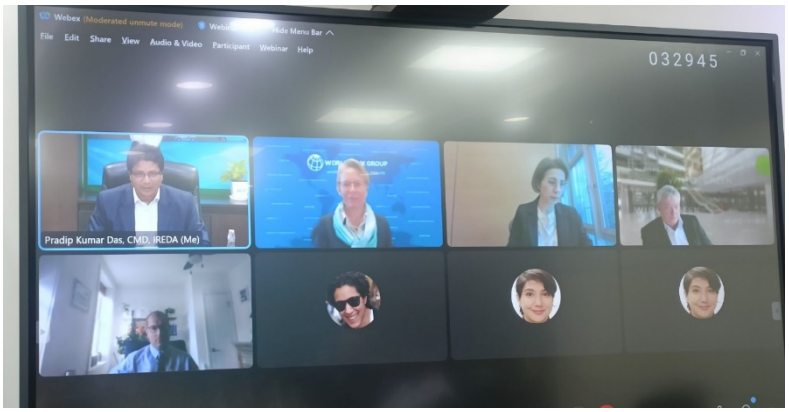

उन्होंने भारत सरकार की नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ), पीएम-कुसुम योजना, आरई परिसंपत्तियों के लिए 'मस्ट-रन' स्थिति, सौर पीवी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, और नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति देने जैसी कई पहलों का उदाहरण देते हुए दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भारत के उदय होने के बारे में जोर दिया। चूंकि भारत का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने का है, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा-स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की मांग महत्वपूर्ण होगी। । ऊर्जा की इस मांग का लगभग 90% नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होने की उम्मीद है। जब तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडारण प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक थर्मल ऊर्जा का भी विकास किया जाएगा। श्री दास ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के पोषण करने के बारे में पिछले 37 वर्षों के दौरान इरेडा द्वारा निभाई गई मातृत्व भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

इस वेबिनार में भाग लेने वाले अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक की विशेष प्रतिनिधि, सुश्री मारिया दिमित्रियादौ; दक्षिण एशिया क्षेत्र, विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, सुश्री फ्रांज़िस्का ओहन्सोरगे; अर्थशास्त्री, प्रॉस्पेक्ट्स ग्रुप, विश्व बैंक के श्री फिलिप केनवर्थी, और ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसर्च मैनेजर, डब्ल्यूआईपीओ ग्रीन के श्री पीटर ओक्सेन शामिल थे ।